नवम्बर 2024
वर्ष 38 संख्या 11
मूल्य 5 रुपये

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी)
की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

प्रतिरोध का स्वर

इस्पात उद्योग के मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम– स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया (सेल) के संयत्रों में 28 अक्तूबर को देश भर में एक दिन की हड़ताल की गई। हड़ताल का आवाह्न सेल में कार्यरत यूनियनों द्वारा किया गया था। यह हड़ताल सेल द्वारा घोषित बोनस नीति के विरुद्ध व बोनस की मांग के लिए तथा मजदूरों की अन्य मांगों पर की गई थी।

पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और प्रशासन की धमकियों को नजर अंदाज करते हुए 28 अक्टूबर 2024 को पश्चिम बंगाल के स्टील प्लांटों में एक दिवसीय व्यापक हड़ताल का आयोजन हुआ। कर्मचारी संघ ने बोनस और 31 महीने के बकाया भुगतान सहित 14 सूत्रीय मांगों पर देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी के गुर्गों ने दुर्गापुर स्टील प्लांट में सेल के गेट पर हड़ताल तोड़ने की कोशिश की, जिससे तनाव पैदा हो गया था, जबकि कर्मचारियों ने हड़ताल की नोटिस पहले ही दे रखी थी।

पश्चिम बंगाल में सेल के तीन स्टील प्लांट हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट, अलॉय स्टील और बर्नपुर में इस्को प्लांट है। हड़ताल में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के साथ–साथ दिहाड़ी श्रमिकों ने भी भागीदारी की।

झारखंड में बोकारो, मध्य प्रदेश में भिलाई तथा ओढिशा में राउरकेला सहित देश के अन्य स्टील प्लांट में हड़ताल सफलता पूर्वक संपन्न हुई। तमिलनाडु में सलेम में सेल के प्लांट में सफलतापूर्वक हड़ताल हुई।

कर्मचारियों ने अपने अधिकारों को छीनने वाली नीतियों के खिलाफ हड़ताल में भागीदारी की। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष में सेल के मुनाफे के बावजूद अधिकारी कर्मचारियों को उचित वेतन और बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं और ना ही नई भर्ती की जा रही है। अधिकांश कर्मचारी दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। कर्मचारियों की कई यूनियनों ने संयुक्त रूप से घोषणा की है कि यदि एक दिन की हड़ताल के बाद भी अधिकारी कर्मचारियों की जायज मांगों को नहीं मानते हैं, तो वह निकट भविष्य में देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल और आंदोलन करेंगे।

सेल के मजदूरों को केन्द्र सरकार की मजदूर–विरोधी नीतियों के कारण हड़ताल पर जाने को मजबूर होना पड़ा है। दरअसल केन्द्र सरकार की नीतियां सार्वजनिक उपक्रमों के खिलाफ हैं तथा वह अपनी गलत नीतियों के परिणामों का बोझ मजदूरों पर डालती रही है।

पीडीएसयू की स्थापना के 50 वर्ष: गौरवशाली इतिहास और छात्र आंदोलन तेज करने का आवाह्न

24 अक्टूबर को, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन (पीडीएसयू) की तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य कमेटियों ने उस्मानिया विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में अर्ध–शताब्दी सभा का आयोजन किया। यह कार्यक्रम पीडीएसयू की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर था और इसमें कई छात्र, पूर्व छात्र और नेता शामिल हुए।

शुरुआत उस्मानिया आर्ट्स कॉलेज से टैगोर ऑडिटोरियम तक जीवंत रैली के साथ हुई, जिसमें "पीडीएसयू जिंदाबाद", "जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो" "जॉर्ज रेड्डी, जेसीएस प्रसाद अमर रहें" जैसे नारे लगाए गए। बाद में पीडीएसयू का चिन्ह – बंद मुट्ठी वाला झंडा – पीडीएसयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बी. प्रदीप द्वारा फहराया गया।

सभा पीडीएसयू के प्रदेश अध्यक्ष पी. महेश और बोनागिरी मधु की अध्यक्षता में हुई। इसका उद्घाटन प्रसिद्ध वैज्ञानिक और कवि गौहर रजा ने किया। उन्होंने ने देश की मौजूदा गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) थोपे जाने की निंदा करते हुए इसे देश पर हमला बताते हुए कहा कि फासीवादी हमले तेज किये जा रहे हैं। सीएए विरोधी संघर्ष को उन्होने एक मिसाल बताया।

गौहर रजा ने कहा कि सरकार छात्रों पर अवैज्ञानिक विचारधारा थोप रही है, जिससे उनकी आलोचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता बाधित हो रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि स्व–घोषित आध्यात्मिक नेताओं (स्वामीजी और बाबाओं) द्वारा जमा की गई संपत्ति से सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा सकती है।

उन्होंने देशभक्ति की आड़ में सरकार की कॉरपोरेट–परस्त नीतियों की निंदा की जो केवल अंबानी जैसे कुछ अमीर व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती हैं। उन्होंने सफल विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ किसानों के आंदोलन की सराहना की जिसने मोदी को कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया।

रजा ने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन (पीडीएसयू) के सदस्यों से छात्रों और लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें भाजपा द्वारा अपनाई गई फासीवादी नीतियों के खिलाफ लड़ने का आवाहृन किया।

प्रो. हरगोपाल और लक्ष्मीनारायण ने भाजपा और आरएसएस की कड़ी आलोचना की और उन पर देश को विभाजित करने और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि यह पाठ्यक्रम में सांप्रदायिक विचारधारा को शामिल करती है। प्रोफेसरों ने शिक्षा के केंद्रीकरण और व्यावसायीकरण के साथ–साथ विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में एबीवीपी से जुड़े व्यक्तियों की नियुक्ति पर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने चेताया कि इन कार्रवाइयों से सामाजिक एकता को खतरा है और सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा मिलता हैं। वक्ताओं ने बढ़ते यौन हमलों और उत्पीड़न का हवाला देते हुए महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर प्रकाश डाला। 'जॉर्ज रेड्डी जीवन रेखालू' की लेखिका कात्यायनी ने कहा कि भाजपा की सांप्रदायिक विचारधारा सम्प्रदायों के बीच संघर्षों को बढ़ावा देती है और इसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रखना है। प्रोफेसरों ने प्रो.

(आगे पृष्ठ 2 पर)

टैगोर हाल, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद : (ऊपर) हाल के एक भाग का फोटो तथा (नीचे) पुस्तक के विमोचन के अवसर पर पी.डी.एस.यू के पूर्व नेता तथा प्रांतों के छात्र नेता

पीडीएसयू के पचास साल पूरे होने पर

माना कि इस जमीं को न गुलजार कर सके
कुछ खार काम तो कर गए, गुजरे जिधर से हम

साहिर

देश भर में और दुनिया के कई हिस्सों में आक्रोश के बीच, PDSU का जन्म हुआ। PDSU का स्थापना सम्मेलन 12, 13 अक्तूबर, 1974 को तत्कालीन आन्ध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था। इस महीने पचास (50) वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर उस्मानिया विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में 24 अक्टूबर को एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी विश्वविद्यालय में पीडीएसयू के बनाने की नींव रखी गई थी, जब जॉर्ज रेड्डी ने सत्तर के दशक के पहले वर्षों में छात्रों को संगठित करना शुरू किया था। उन्होनें जो विभिन्न स्टडी सर्कल आयोजित किए और जो पीडीएस बैनर जारी किए गए, वे 1974 में पीडीएसयू के गठन के पूर्ववर्ती थे, जब कई जिलों में पीएसएफ, पीएस, एसएफ आदि जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों का 1974 में इस मंच में विलय हो गया। यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों और देश में भी अशांति और उथल–पुथल का दौर था। यह एक ऐसा दौर था जिसमें हमने छात्र आंदोलनों का एक ऐसा सिलसिला देखा जिसने सरकारों को हिला दिया। साठ के दशक के उत्तरार्ध में सत्तर के दशक तक वह आक्रोश था। फ्रांसीसी छात्रों के आंदोलन, सोवेटो छात्रों के विद्रोह, कई लैटिन अमेरिकी देशों में विद्रोह और अमेरिकी साम्राज्यवादी आक्रामकता के खिलाफ वियतनामी लोगों द्वारा प्रतिरोध ने गहराई से युवाओं के मन को प्रभावित किया था। और फिर चे ग्वेरा थे। इस देश में इस अवधि में किसान और आदिवासी संघर्षों, नक्सलबाड़ी, श्रीकाकुलम, गोदावरी घाटी की बाढ़ आ गई जिन्होंने युवाओं और छात्रों की चेतना को आकार देने में भूमिका निभाई। इसी परिवेश में क्रांतिकारी छात्र आंदोलन के बीज बोए गए थे और इस प्रकार पीडीएसयू का जन्म हुआ।

पिछले पचास वर्षों में पीडीएसयू ने छात्र समस्याओं के समाधान के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ीं। आपातकाल से पहले के समय में इसने बेहतर सुविधाओं और सामाजिक कल्याण, छात्रावासों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए लड़ाई लड़ी, बस किराया वृद्धि के खिलाफ आंदोलन किया, मूल्य वृद्धि के खिलाफ अभियान चलाया। इसने ओयू उस्मानिया विवि प्रशासन द्वारा ग्यारह पीडीएसयू कार्यकर्ताओं के निष्कासन के खिलाफ एक निरंतर, राज्य स्तरीय सफल आंदोलन का निर्माण किया। यह 1974 में ऐतिहासिक रेल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में खड़ा हुआ और इसके पांच कार्यकर्ताओं को डिफेंस ऑफ इण्डियन रूल्स (डीआईआर) के तहत जेल में डाल दिया गया। हर साल 14 अप्रैल को जॉर्ज स्मारक बैठकें आयोजित की जाती थीं, जिसमें हजारों छात्रों को आकर्षित होते था। आपातकाल के बाद का समय संगठन के पुनरुद्धार का दौर था और छात्र समुदाय की विभिन्न समस्याओं पर छात्र आंदोलनों की एक श्रृंखला हुई। इस अवधि में विशाल लामबंदिया हुई और कई जुझारू संघर्ष किए गए। जॉर्ज, जम्पाला, श्रीहरि की याद में शहीद स्मृति सभाओं में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए।

पीडीएसयू के इतिहास में 1981 में विशाखापत्तनम में राज्य सम्मेलन को पीडीएसयू सदस्यों द्वारा राजकीय दमन के खिलाफ किये गए जुझारु प्रतिरोध के लिए याद किया जाएगा जिसमें कॉमरेड समाबैया वराहालु की शहादत हुई। अस्सी के दशक के उत्तरार्ध में पीडीएसयू ने कैपिटेशन शुल्क के खिलाफ आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई।

पचास साल ऐसे रहे हैं जिनमें कई उतार–चढ़ाव आए हैं और इस अवसर पर यह आवश्यक है कि हम आत्मनिरीक्षण करें और भविष्य की दिशा तय करें। पिछले संघर्षों के आख्यानों को हमें उत्साहित करना चाहिए, जबकि पिछले अनुभवों से सीखना चाहिए। हमें वर्तमान परिस्थितियों का ठोस और सही मूल्यांकन करना चाहिए जिसमें हम आज स्थित हैं। हमें वर्तमान चुनौतीपूर्ण स्थिति में आगे बढ़ने के लिए रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है।

हम एक ऐसे वातावरण में पीडीएसयू के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं जिसमें शिक्षा प्रणाली कॉरपोरेट, निजी क्षेत्र के अधीन आ गई है और पंगु सरकारी क्षेत्र ने सार्वजनिक शिक्षा को बेसहारा छोड़ दिया है। विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए दरवाजे एकदम खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही केंद्र की सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का भगवाकरण करने का अभियान भी चलाया गया है। शिक्षा प्रणाली में जो भी थोड़े–बहुत धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उन्हें छीनने के लिए आरएसएस–भाजपा के राजनीतिक प्रोजेक्ट को शिक्षा में घुसाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के भगवाकरण का एक तरीका है। सब कुछ राष्ट्र व राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हो रहा है। राष्ट्र के बारे में उनकी धारणा संकीर्ण और सांप्रदायिक है और हिटलर के फासीवाद के समान ही है। विशाल विविधताओं वाले देश को हिंदू राष्ट्र नामक एक अखंड इकाई में बदलने करने की कोशिश की जा रही है।

हम इस अवसर को ऐसी स्थिति में मना रहे हैं जब देश में अर्थव्यवस्था वास्तव में चमक नहीं रही है, बल्कि गंभीर संकट में है, बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है, असमानताएं और धन संकेद्रण बढ़ रहा है। विरोध और असंतोष की आवाजों को दबाना आज का नियम है और नए आपराधिक कानून इसी दिशा में बनाए गए हैं। यह स्थिति प्रगतिशील छात्र आंदोलन के समक्ष कई चुनौतियां पेश करती है और इस अवसर पर हमें इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। आइए हम उन शहीदों– जार्ज, जम्पाला, श्रीहरि, मधुसूदन राज, रंगवल्ली, मारोजू वीरन्ना, चांद पाशा, चेरालु, वीरा रेड्डी, कोला शंकर, संबैया, रमनैह, बिक्षम को याद करें जिन्होंने पीडीएसयू बनायी और लोगों के हित में अपने प्राणों की आहुति दी और इन शहीदों के सपने को साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं।

प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन (PDSU)

(महेश और नागराज द्वारा जारी)

पीडीएसयूः उस्मानिया विश्वविद्यालय में कार्यक्रम

(पृष्ठ 1 से आगे)

साईबाबा की मौत को भाजपा की दमनकारी नीतियों का परिणाम बताया, जिसमें झूठे मामले दर्ज करना और पार्टी के कॉरपोरेट–परस्त एजेंडे का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं को जेल में डालना शामिल है।

बी. प्रदीप, एस. वेंकटेश्वर राव, पी. प्रसाद, चिट्टी पति वेंकटेश्वरलू और एम. श्रीनिवास सहित पीडीएसयू के पूर्व नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीडीएसयू का गठन नक्सलबाड़ी और श्रीकाकुलम गोदावरी घाटी संघर्षों से प्रेरित होकर किया गया था। उन्होंने कहा कि पीडीएसयू छात्र आंदोलनों में मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है। उन्होंने छात्रों में क्रांतिकारी भावना पैदा करने के लिए पीडीएसयू की सराहना की। पूर्व छात्र नेताओं ने अपने अनुभव साझा किये तथा वर्तमान छात्रों से अपने रचनात्मक प्रयासों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने समाज में बढ़ती आर्थिक और सामाजिक असमानताओं और जाति उत्पीड़न की निंदा की और पीडीएसयू से एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होने तक अनवरत संघर्ष जारी रखने का आग्रह किया।

मंच पर (बायें से) पी.डी.एस.यू. के पूर्व अध्यक्ष का. पी. प्रसाद, का. एस. वैंकटेश्वर राव तथा का. बी. प्रदीप, उद्घाटनकर्ता डा. गौहर रजा, प्रो. हरगोपाल, प्रो. लक्ष्मीनारायण व कात्यायनी

कार्यक्रम में जॉर्ज रेड्डी, जेसीएस प्रसाद, श्रीहरि, कोला शंकर, रंगावल्ली और चेराला सहित छात्र शहीदों को सम्मानित किया गया।

अमनदीप सिंह (पंजाब पी.एस.यू.), रोहित सोलंकी (दिल्ली), अत्रेयो मंडल (पश्चिम बंगाल), शाहनवाज खान (उत्तर प्रदेश), मुन्ना कुमार (बिहार), कान्हू चरण (ओडिशा), अंबू (तमिलनाडु रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट यूथ फेडरेशन), सरवर जहां (असम एनआईएसए), सूर्या (कर्नाटक एसएफपीडी), मनमोहन (पूर्व जेएनयू छात्र) सहित विभिन्न राज्यों के नेताओं और बिरादराना संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाजपा की सांप्रदायिक और फासीवादी नीतियों के खिलाफ एकताबद्ध राष्ट्रीय छात्र आंदोलन की आवश्यकता की बात की। उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह ब्राह्मणवादी मनु स्मृति, शिक्षा को कंपनियों के हवाले करने और शिक्षा प्रणाली के केंद्रीकरण को बढ़ावा देती है और इसके प्रतिरोध का आह्वान किया।

इस अवसर पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश निम्मा नारायण, पीडीएसयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुरुवरेड्डी, वी. शंकर और प्रोफेसर कोंडा नागेश्वर राव और समुनाथ ने एक लेखों के संकलन "पोरु पिडिकिल्लु" (संघर्ष की मुट्ठी) को जारी किया।

प्रोफेसर कासिम, विनय बाबू, सामना, पीओडब्ल्यू की झाँसी और संध्या, पीडीएसयू की पूर्व नेता अंबिका ने अरुणोदय के नेताओं वेणु और दासू के साथ, पीडीएसयू के आंदोलन और शहीदों की कहानियों के बारे में एक संगीत सीडी जारी की।

आर. गुरुवरेड्डी, गोरेपति माधवराव, वी. शंकर, प्रो. कासिम, प्रो. कोंडा नागेश्वर राव और अंबिका सहित पीडीएसयू के पूर्व छात्र नेताओ ने विचार रखे।

पीडीएसयू के राज्य सचिव एसवी श्रीकांत और पी. नागराजू और आंध्र प्रदेश के राज्य अध्यक्ष सचिव ई. भूषणम, एल. राजशेखर, के. भास्कर और विनोद ने कहा कि पीडीएसयू केंद्र और राज्य सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है और लोगों का जीवन स्तर गिर रहा है। उन्होंने कहा, 'पीडीएसयू शिक्षा, रोजगार के अवसरों और बेहतर जीवन स्थितियों के लिए लड़ेगी।

कार्यक्रम में डॉ. पिटला सरिता, डॉ. ई. उपेन्द्र, डॉ. एन. सौंदर्या, गोपीकृष्ण, डॉ. दुब्बा रंजीत और डॉ. अनुराधा सहित कई पूर्व और वर्तमान छात्रों ने भाग लिया।

पीडीएसयू की 50वीं वर्षगांठ का समारोह जबरदस्त सफल रहा, जिसका समापन उस्मानिया विश्वविद्यालय में एक भव्य समापन समारोह में हुआ। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से पहले राज्य भर में जिला–स्तरीय छात्र सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिससे दो महीने तक चलने वाले उत्सव के माहौल को बढ़ावा मिला।

उस्मानिया विश्वविद्यालय के भव्य कार्यक्रम ने छात्रों को सशक्त बनाने और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए पीडीएसयू की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। संगठन के समर्पण और व्यापक समर्थन ने सुनिश्चित किया कि 50वीं वर्षगांठ समारोह एक सफल कार्यक्रम रहा।

पीडीएसयू तेलंगाना राज्य कमेटियाँ।

जन आंदोलनों की रक्षा में, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष तेज करो

इस साल के लोकसभा चुनाव में बहुमत खोने और एनडीए सहयोगियों के साथ गठबंधन सरकार बनाने के लिए मजबूर होने के बावजूद आरएसएस–भाजपा लोकतांत्रिक अधिकारों पर लगातार हमले कर रही है। विशेषकर कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के नेतृत्व में चल रहे जन संघर्ष उनके हमले का विशेष निशाना रहे हैं। जन आंदोलनों के खिलाफ हमलों के साथ–साथ, आरएसएस–भाजपा अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपने हमले जारी रखे हुए हैं। यूपी और असम जैसे अपने गढ़ों में, आरएसएस–भाजपा विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ हमले तेज कर रहे हैं।

यूएपीए लोगों के विभिन्न वर्गों के आंदोलनों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हमले का एक पसंदीदा हथियार बनकर उभरा है। जमानत देने के खिलाफ इसके कड़े प्रावधानों के कारण जमानत हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाता है जो बहुत लंबे समय तक कैद में रहने के बाद मिलती है, जिस दौरान मुकदमा भी नहीं चलता और वह भी कुछ ही मामलों में मिलती है। कई छात्र कार्यकर्ता 2020 की शुरुआत से बिना किसी मुकदमे के जेलों में बंद हैं और इस तरह यह प्रक्रिया ही एक सजा बन गई है। बार–बार यह कहने के बावजूद कि जमानत देना नियम होना चाहिए और जेल अपवाद होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट यूएपीए के तहत मामलों में ठीक इसके विपरीत व्यवहार कर रहा है। वह यूएपीए के तहत फंसाए गए लोगों की स्वतंत्रता को बरकरार रखने में विफल है और विभिन्न बहानों पर जमानत याचिकाओं पर विचार करने से इनकार करता रहा है। दरअसल, वताली मामले के फैसले के जरिए शीर्ष अदालत ने यूएपीए के तहत जमानत पाना खुद ही बेहद मुश्किल बना दिया है। केवल सुरक्षा एजेंसियों की शिकायतों के आधार पर लोगों को कैद में रखने का यह दृष्टिकोण, आरोपों की न्यायिक जांच को दरकिनार करना, इस अवधारणा के खिलाफ है कि सुरक्षा एजेंसियों के पास न्यायिक जांच के बिना किसी को भी 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया की विषय–वस्तु और ऐसे मामलों में कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करने के मूल आधार को ही नकार दिया जाता रहा है।

ऐसे घोर दमनकारी कानूनों से लैस और राज्य की ताकत से लैस, जो लगातार मजबूत होती जा रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले दो वर्षों में, 2026 तक, भारत को माओवाद से मुक्त देश बनाने का दावा किया है। यह लोगों के संघर्षों के खिलाफ थोक हमले का हिस्सा है। इसे आरएसएस–भाजपा सरकार के दूसरे पहलू, "अर्बन नक्सल" पर हमला करने की नीति से जोड़कर देखा जाना चाहिए। यह आरएसएस के प्रचारकों द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसमें वे सभी लोग शामिल हैं जो संघर्षरत लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ते हैं और उत्पीड़ित और शोषितों के साथ खड़े होते हैं।

जबकि देश के लोग गरीबी और अभाव, भूख और कुपोषण, भेदभाव और उत्पीड़न, बढ़ती बेरोजगारी और तेजी से बढ़ती असमानता से कराह रहे हैं, आरएसएस–भाजपा सरकार की प्राथमिकता देश को एफडीआई का पसंदीदा गंतव्य बनाना है। आरएसएस–भाजपा सरकार, अधिकांश लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए काम करने के बजाय, विदेशी और घरेलू कॉरपोरेट के लिए व्यापार करने में आसानी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो उनके श्रम के बढ़ते शोषण और प्राकृतिक संसाधनों की लूट को सुविधाजनक बनाने का एक और शब्द है। आरएसएस–भाजपा सरकार का ध्यान शिक्षित बेरोजगारों सहित बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को सार्थक रोजगार प्रदान करने के बजाय अमीरों को और अमीर बनाने और गरीबों को और गरीब बनाने पर केंद्रित है। आरएसएस–बीजेपी सरकार की प्राथमिकताएं, भारत के बहुसंख्यक लोगों की आवश्यकताओं के साथ विपरीत संबंध रखती हैं।

अमित शाह की घोषणा को आरएसएस–भाजपा सरकार के छत्तीसगढ़ के खनिज और संसाधन समृद्ध वन क्षेत्रों को विदेशी और अंबानी और अडानी जैसे घरेलू कॉरपोरेट द्वारा शोषण के लिए उपलब्ध कराने के प्रयास के प्रकाश में देखा जाना चाहिए। आदिवासियों को इस क्षेत्र से बाहर निकालने या अपने आवास और आजीविका के विनाश में मूकदर्शक बनाने के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। यह कॉरपोरेट की सेवा में राज्य की शक्ति का सबसे जबरदस्त और घृणित उपयोग है, जिसे कोलंबस के बाद सबसे बड़ी भूमि हड़पना बताया गया है। समृद्ध संसाधनों की यह लूट–खसोट इन कॉरपोरेट के लिए सबसे लाभदायक व्यवसाय है और यह सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से किया जाता है, जो दोनों के बीच के गठजोड़ को खुला और नंगा कर देती है। यह छत्तीसगढ़ में नए सिरे से शुरू हुए आक्रमण को परिप्रेक्ष्य में रखता है। जनवरी 2024 से अब तक 200 से अधिक आदिवासी और कार्यकर्ता सुरक्षा बलों द्वारा मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं।

और इस उद्देश्य के लिए यह आक्रामकता केवल छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है। पूर्वोत्तर में भी, विदेशी और घरेलू कॉरपोरेट के शोषण के लिए जमीन साफ करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का आक्रमण बहुत स्पष्ट है; जितना ये वर्तमान सरकार के करीब हैं उतना ही उनके लाभ अधिक है। यह वास्तव में देशव्यापी अभियान है।

लोगों के साथ अपने विश्वासघात को छुपाने और अपने कुशासन के खिलाफ लोगों के चुनावी फैसले को रद्द करने के लिए, आरएसएस–भाजपा अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ अपने हमले तेज कर रहे हैं। वे सांप्रदायिक विभाजन को गहरा कर रहे हैं जैसा कि यूपी के मुख्यमंत्री के 'बटोगे तो कटोगे' वाले बयान से स्पष्ट है। सामाजिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण के खिलाफ शोषितों–उत्पीड़ितों के संघर्ष को भटकाने की भी यह उनकी मुहिम है। असम के मुख्यमंत्री सांप्रदायिक माहौल गर्म रखने के लिए नियमित आधार पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ विषवमन करते हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को गहरा करने के उनके नापाक प्रयास उन लोगों की जरूरतों के विपरीत हैं जो भोजन, आवश्यकताएं और नौकरियां, शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति की मांग करते हैं। लोगों को इनके लिए संघर्ष करने के लिए एकता बनाने की जरूरत है और इसके लिए जनता को सांप्रदायिक और अन्य संकीर्ण आधारों पर विभाजित करने के आरएसएस–भाजपा के प्रयासों को हराना होगा।

जबकि पिछले लोकसभा चुनावों के बाद आरएसएस–भाजपा के फासीवादी आक्रमण की गति कुछ कम हो गई थी, वे इस नुकसान से उबरने और अपने फासीवादी अभियान को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यह लोगों के विभिन्न वर्गों के जन आंदोलनों और संघर्षों को तेज करने की आवश्यकता को एजेंडे में लाता है। यह संघर्षरत लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष को तेज करने, जन आंदोलन के कार्यकर्ताओं की रक्षा करने और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने और उनके जीवन और संपत्तियों के खिलाफ हमलों के खिलाफ लोगों को संगठित करने की आवश्यकता को सामने लाता है। लोगों को विभाजित करने और दबाने की सत्तारूढ़ फासीवादी ताकतों की साजिशों को हराने और जन संघर्षों, विशेषकर मजदूरों और किसानों के संघर्षों को खड़ा करने के लिए यह संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए और प्रतिक्रियावादी शासक ताकतों के हमलों के खिलाफ संघर्ष फासीवादी ताकतों और उनके शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लोगों के संघर्ष का बहुत महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है।

(न्यू डेमोक्रेसी के अक्तूबर 2024 अंक के संपादकीय का हिन्दी अनुवाद)

बिजनौर (उ.प्र.) : मिड-डे मील रसोईयों द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन

प्रगतिशील रसोईया संगठन जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश ने अपनी मांगों को लेकर 27 अक्टूबर 2024 को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जिलाधिकारी बिजनौर के माध्यम से प्रेषित किया।

प्रगतिशील रसोईया संगठन की महिलाएं सुबह 11:00 से नुमाइश ग्राउंड बिजनौर के निकट इकट्ठा हुई जहां पर एक सभा की जिसकी अध्यक्षता श्रीमती मुनेश ने की तथा संचालन बबीता शर्मा ने किया। सभा को रेखा देवी, बीना, पूजा, जयाप्रदा, अंशु, मीनू (धामपुर) वंदना, सुमन, पुष्पा देवी, ममता, सविता, जमीरन, नूरी, सोनम, उषा देवी, पूजा, सुमन, लीलावती (ब्लॉक किरतपुर) शाइस्ता, शाहीन, नाजरीन, बबीता, सुनीता, नजीबाबाद, पवन देवी, अनीता सुमन देवी, जयवती, सुमन, लीलावती (बिजनौर) आदि सभी रसोइयों ने अपने–अपने क्षेत्र में सभाएं करके प्रदर्शन की भूमिका तैयार की। धामपुर में रेखा देवी और बबीता के द्वारा रसोइयों की बैठक आयोजित कर तैयारी की गई। किरतपुर में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को मांग पत्र प्रेषित किया गया। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष शमशाद हुसैन तथा जिला सचिव सुभाष चंद्र ने रसोइयों का पूरा सहयोग किया।

जोरदार नारेबाजी करती हुई हाथों में तख्तिया लिए रसोईया जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची और अपनी मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को और एडीएम बिजनौर को मांग पत्र दिया जिसमें रसोइयों का 5 माह का रुका बकाया दीपावली से पहले दिलाने, सभी रसोइयों को नियमित कर रु, 18000 वेतन देने, मनमाने तरीके से रसोइयों को विद्यालय से न हटाए जाने, आंगनबाड़ी के बच्चों का खाना जो रसोइयों के द्वारा बनाया जा रहा है उसका पैसा दिलाने, रसोइयों को राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड दिलाने, उनके आवास बनवाने आदि मांगे की गइ। रसोइयों ने जिला मुख्यालय पर घोषणा की कि वह अपनी लड़ाई के लिए लखनऊ और दिल्ली तक जाएगी और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। 500 से अधिक रसोइयों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

रसोइयों के कार्यक्रम को एल ई यू जिला प्रशासन ने भी गंभीरता से लिया और शासन को पिछले महीने ही रिपोर्ट भेज दी थी। 30 अक्टूबर 2024 को रसोइयों के खाते में रु. 5000 प्रदेश सरकार के द्वारा भेजे गए हैं। यह संगठित होकर संघर्ष करने का परिणाम है और उनकी एक जीत है। इससे संघर्ष आगे बढ़ाने में उन्हें हिम्मत व हौसला मिलेगा।

जम्मू–कश्मीर और हरियाणा में चुनाव : मिश्रित परिणाम जन

जम्मू–कश्मीर : कश्मीर घाटी में आरएसएस–भाजपा को नकार कर दिया गया

हरियाणा और जम्मू–कश्मीर में चुनावों के नतीजे 8 अक्टूबर, 2024 को घोषित किए गए। अप्रैल–जून 2024 के दौरान लोकसभा चुनावों के बाद, जिसमें आरएसएस–बीजेपी ने अपना बहुमत खो दिया था और केंद्र में अपने एनडीए सहयोगियों के साथ सरकार बनाई थी, ये पहले चुनाव थे। जम्मू–कश्मीर और हरियाणा में इन चुनावों के नतीजे राज्यों में भिन्न कारकों को दर्शाते हैं। इन नतीजों से यह भी पता चलता है कि जब मुख्य शासक वर्ग की पार्टियों – भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी चुनावी लड़ाई होती है तो चुनावी मुकाबला कैसा आकार लेता है विशेषकर हिंदी भाषी राज्यों में।

जम्मू–कश्मीर चुनाव में कश्मीर घाटी में आरएसएस–बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिल पाया। तमाम कोशिशों और तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद आरएसएस–बीजेपी घाटी में एक भी सीट नहीं जीत सकी, हालांकि वे जम्मू क्षेत्र में अधिकांश सीटें (29 सीटें) जीतने में कामयाब रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 सीटों के साथ सदन में सबसे अधिक सीटें (42) जीतीं, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिलीं। एक अन्य प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी पीडीपी की सीटें घटकर मात्र 3 रह गईं। सीपीएम ने अपनी सीट बरकरार रखी। 2014 में हुए पहले के चुनावों की तुलना में कांग्रेस और पीडीपी दोनों ने अपने वोट शेयर का एक बड़ा हिस्सा खो दिया, जबकि एनसी और बीजेपी ने अपने वोट शेयर में मामूली वृद्धि की। एनसी–कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत सीटें हासिल कीं।

जम्मू–कश्मीर चुनाव परिणामों ने जम्मू–कश्मीर में खंडित जनादेश होने के आरएसएस–भाजपा गेम प्लान को विफल कर दिया, जहां उसे निर्दलीय और छोटे दलों की मदद से अपना मुख्यमंत्री सत्ता में लाने की उम्मीद थी। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि उन्होंने चयनित निर्दलीय उम्मीदवारों और कुछ पार्टियों के उम्मीदवारों को समर्थन देते हुए घाटी में कम संख्या में उम्मीदवार उतारे थे। इसके अलावा, जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल के पास विधानसभा के 5 सदस्यों को नामित करने की शक्ति है, जो आरएसएस–भाजपा को उम्मीद थी कि यह जम्मू–कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री लाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन आरएसएस–बीजेपी द्वारा चालाकी से बनाई गई इस रणनीति को जम्मू–कश्मीर के लोगों, खासकर कश्मीर घाटी के लोगों ने नाकाम कर दिया। आरएसएस–बीजेपी को पता था कि कश्मीर घाटी के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के क्रूर दमन, अनुच्छेद 370 को रद्द करने और अनुच्छेद 35ए को निरस्त करने के खिलाफ हैं। फिर भी जोड़तोड़ के माध्यम से आरएसएस–बीजेपी यह दिखाना चाहती थी कि जम्मू–कश्मीर के लोगों ने उनके द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन किया है, यानी जम्मू–कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विघटित करने और संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेदों को रद्द करने का समर्थन किया है।

चुनाव परिणामों के अनुसार जम्मू–कश्मीर में लोगों ने आरएसएस–भाजपा सरकार द्वारा जम्मू–कश्मीर के लोगों के खिलाफ उठाए गए कदम और 'त्रिशंकु सदन' के उनके गेम प्लान को नकार दिया है। कश्मीर घाटी में लोगों का वोट आरएसएस–भाजपा सरकार द्वारा उठाए गए अलोकतांत्रिक कदमों के खिलाफ है और यह उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए वोट है। इंजीनियर रशीद की पार्टी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से भारी जीत हासिल की थी और चुनाव के दौरान रिहा कर दिए गए थे, का प्रदर्शन भी कश्मीर के लोगों की इन चिंताओं के कारण बहुत खराब रहा। कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा का मुद्दा 5 अगस्त, 2019 को आरएसएस–भाजपा सरकार के कार्यों के खिलाफ गुस्से में परिलक्षित हुआ। उन्होंने वोट से एनसी–कांग्रेस गठबंधन को बहुमत दिला दिया।

परंतु जम्मू–कश्मीर के लोगों की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। विभाजन के बाद जम्मू–कश्मीर एक राज्य नही है और वहां की निर्वाचित सरकार के पास संविधान में राज्यों के लिए दर्ज राज्य सरकार के अधिकार नहीं हैं। आरएसएस–भाजपा ने वहां बार–बार राज्य का दर्जा बहाल करने का वायदा किया है लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया है। केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार की शक्ति सर्वविदित है क्योंकि दिल्ली के अनुभव से साबित होता है कि इसे एक राज्य से कम का दर्जा दिया गया था और यह चल रहा है।

जम्मू–कश्मीर में इन परिणामों का मुख्य निश्कर्ष यह है कि आरएसएस–बीजेपी का दावा कि उन्होंने जम्मू–कश्मीर के लोगों के हित में काम किया है और उनके कदमों को लोगों का समर्थन प्राप्त है, उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। यह ध्यान रखना उचित है कि जम्मू–कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने अन्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लोग भी लगातार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में लद्दाख में आरएसएस–बीजेपी को खारिज कर दिया गया था। ये चुनाव स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि लोगों के हितों में काम करने का आरएसएस–भाजपा का दावा पूरी तरह से फर्जी था और वे केवल जम्मू–कश्मीर की विशेष स्थिति, विशेष रूप से अनुच्छेद 370 को रद्द करने के अपने दीर्घकालिक एजेंडे को लागू कर रहे थे। यह उनके हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट के मुख्य मुद्दों में से एक रहा है। इसमें उन्हें 2019 में सत्ता में वापसी के बाद शासक वर्ग के कई क्षेत्रीय दलों का समर्थन प्राप्त था। यह चौतरफा हिंदुत्ववादी आक्रामण था। उनके कदम जम्मू–कश्मीर के लोगों के खिलाफ थे और वहां के लोगों ने उनका विरोध किया और लोगों ने इन चुनावों में आरएसएस–भाजपा को खारिज करके अपना विरोध जारी रखा। चुनाव नतीजों ने घाटी के लोगों के आरएसएस–भाजपा से खुश होने के उनके बहुप्रचारित झूठ की पोल खोल दी है।

आरएसएस–बीजेपी को अस्वीकार करने के अलावा यह चुनाव परिणाम लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आंदोलन के विकास में मदद कर सकता है, हालांकि इस आंदोलन को गंभीर राज्य दमन का अभी भी सामना करना पड़ेगा। तब भी, लोग अब आंदोलन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं क्योंकि चुनावों में आरएसएस–भाजपा शासन की उनकी अस्वीकृति प्रदर्शित हो गई है। जम्मू–कश्मीर में फासीवादी ताकतों को झटका, जिसे उन्होंने अपना परीक्षण मामला बना लिया था, एक अच्छा विकास है।

हरियाणा : करीबी मुकाबले में आरएसएस–बीजेपी ने कांग्रेस को हराया

राजधानी दिल्ली की तीन तरफ से सीमा से लगे हिंदी भाषी राज्य हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर ज्यादा नजरें टिकी रहीं। हरियाणा में आरएसएस–भाजपा के कुशासन के खिलाफ राज्य के अधिकांश लोगों में गुस्सा देखा जा सकता था और व्यापक रूप से उनकी हार का अनुमान लगाया जा रहा था। इस राज्य में चुनाव ज्यादातर कांग्रेस और आरएसएस–भाजपा के बीच सीधे मुकाबले के रूप में हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को 5–5 सीटें मिली थीं। हालाँकि, कांग्रेस–आप गठबंधन को आरएसएस–भाजपा की तुलना में 1.5 % अधिक वोट मिले थे और लोकसभा चुनाव में उसने 46 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई थी, जबकि आरएसएस–भाजपा को 44 विधान सभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है जबकि भाजपा ने शहरी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है। यह काफी हद तक हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में एसकेएम के नेतृत्व में किसान आंदोलन के प्रभाव के कारण था।

लोकसभा चुनाव के बाद से लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी। लोगों के इस बढ़ते गुस्से को भांपते हुए आरएसएस–बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ समर्थन हासिल करने के लिए अपने साढ़े नौ साल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ओबीसी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया था। यह कदम लोगों के गुस्से को दूर करने के लिए भी था। फिर भी लोगों का आक्रोश जारी रहा और यह नाराजगी इस तथ्य से स्पष्ट है कि आरएसएस–भाजपा सरकार के ग्यारह में से नौ मंत्री चुनाव हार गए और जो दो मंत्री जीते, वे बहुत कम अंतर से जीते। उनकी सहयोगी जेजेपी का सफाया हो गया और पूर्व उपमुख्यमंत्री को अपनी जमानत भी गंवानी पड़ी।

इस चुनाव में कांग्रेस के जीतने का अनुमान था पर वह हार गई। पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ सफलता से उत्साहित कांग्रेस ने इससे उचित सबक नहीं लिया। उन्होंने इसे अपनी जीत माना और राहुल गांधी के नेतृत्व का समर्थन जबकि सह आरएसएस–भाजपा के दस साल पुराने कुशासन के खिलाफ लोगों के गुस्सा था जो उनके द्वारा कॉरपोरेट की सेवा और लोगों के संघर्षों के दमन से चिह्नित है। इस गलत आधार पर, चापलूसों और नव–धर्मांतरितों द्वारा प्रचारित, कांग्रेस ने हाल के लोकसभा चुनावों में बहुत करीबी चुनावी लड़ाई के बावजूद अपनी जीत सुनिश्चित मान ली। उन्होंने 'आप' से गठबंधन तोड़ दिया और खुद को लगभग दो तिहाई जीत के प्रति आश्वस्त माना। हालाँकि आप ने कोई भी सीट नहीं जीती और उसे केवल 1.79% वोट मिले, फिर भी यह कांग्रेस और आरएसएस–भाजपा के बीच के अंतर से दोगुने से भी अधिक था। कांग्रेस का वोट शेयर 39.09% रहा (उसकी सहयोगी सीपीएम के साथ 39.34% जिसने एक सीट पर चुनाव लड़ा था) और आरएसएस–बीजेपी का वोट शेयर 39.94% था। पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में कांग्रेस को 11% अधिक वोट मिले, जबकि भाजपा को 3% से अधिक वोट मिले। ऐसा मुख्यतः चुनावों में जेजेपी के पतन के कारण हुआ।

उनके आचरण से पता चलता है कि कांग्रेस जैसी शासक वर्ग की पार्टियाँ वास्तव में वर्तमान सत्तारूढ़ आरएसएस–भाजपा को फासीवादी नहीं मानती हैं, हालाँकि वे ऐसी आवाजें तब उठाती हैं जब यह उनके लिए उपयुक्त होता है। उन्होंने इस चुनाव को सत्ता में आने के अवसर के रूप में देखा और आरएसएस–भाजपा को हराने के सवाल को पृष्ठभूमि में धकेल दिया।

कांग्रेस ने पूरा चुनाव भूपिंदर सिंह हुड्डा पर छोड़ दिया और अपने सभी अन्य नेताओं को हाशिये पर डाल दिया। कथित तौर पर 90 उम्मीदवारों में से 76 कांग्रेस के भीतर हुड्डा खेमे के थे। इससे अन्य नेताओं में गुस्सा पैदा हो गया था और उनके समर्थन आधार में भी इसका असर हो गया था। कुमारी शैलजा की नाराजगी जग जाहिर थी और वह कई दिनों के लिए प्रचार अभियान से हट गईं। यह महज नेताओं के बीच का संघर्ष नहीं था बल्कि इसका असर दलितों के बीच कुमारी शैलजा के जनाधार पर भी पड़ा। इसे भुनाने के लिए आरएसएस–बीजेपी ने कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का न्यौता तक दे डाला। करीबी मुकाबले वाले चुनावों में दलितों के वोट महत्वपूर्ण थे, क्योंकि मतदाताओं में उनकी हिस्सेदारी 20.17% थी, जिनमें से ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में कामगार थे। वे संख्या में जाटों के बाद दूसरे स्थान पर हैं। जाट जमीन वाले किसानों में प्रमुख हैं, एक ऐसा वर्ग है जो हरियाणा के बड़े हिस्से में जमीन के मालिक है, दक्षिण हरियाणा को छोड़कर जहां ग्रामीण क्षेत्रों में यादव मुख्य भूस्वामी समुदाय हैं। बीजेपी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 सीटों में से 8 सीटें हासिल कीं, जो पिछली बार की तुलना में दोगुनी है। मेवात का वह इलाका जहां मतदाताओं में मेव मुसलमानों की बड़ी संख्या है, आरएसएस–बीजेपी के खिलाफ खड़ा रहा। शहरी क्षेत्र भाजपा का गढ़ बने रहे और ऊंची जातियों और पंजाबियों का बड़ा वर्ग उनके साथ रहा।

जबकि कांग्रेस को किसानों के आंदोलन से लाभ हुआ, जिसके कारण अपनी जमीन पर खेती करने वाले भूस्वामी समुदाय – जाटों ने कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस ने किसानों को अन्य समुदायों से अलग करके, विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों से, जो अपनी भूमि और कृषि के क्षेत्र में कॉरपोरेट आक्रमण के खिलाफ संघर्ष में उनके सहयोगी हैं, किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाया। चूंकि कांग्रेस का इस संबंध में आर.एस.एस.–भाजपा से कोई नीतिगत

आंदोलनों को तेज करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं

अंतर नहीं है, इसलिए चुनावी क्षेत्र से परे उनके मुद्दों पर उसका कोई ध्यान नहीं था।

इनमें से कुछ अन्तर हरियाणा में किसान आंदोलन के दौरान भी स्पष्ट थे। उत्तरी और मध्य हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का आंदोलन बहुत तीव्र था लेकिन दक्षिण हरियाणा में उतना तीव्र नहीं था। इसके कारण संबंधित क्षेत्रों में कृषि अर्थव्यवस्था में निहित हैं। दक्षिण हरियाणा बड़े औद्योगिक उद्यमों और महानगरों– गुरुग्राम और फरीदाबाद का घर है। पानी की कमी ने इस हिस्से में कृषि कार्यों को प्रभावित किया, जिससे स्व–खेती करने वाले किसानों को अधिक कृषि अधिशेष नहीं मिलता। यह एक कारण था कि इस क्षेत्र में किसान आंदोलन ग्रामीण हरियाणा के अन्य हिस्सों की तरह तीव्र नहीं था। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता पंजाब में इस तरह के समर्थन की तुलना में शहरी क्षेत्रों में किसानों के आंदोलन को अपेक्षाकृत कम समर्थन था, जबकि ग्रामीण हरियाणा के बड़े हिस्से में आंदोलन काफी तीव्र था। ये वो कमजोरियां थीं जिनका इस्तेमाल आरएसएस–भाजपा ने किया। कांग्रेस किसानों के गुस्से को महज भुनाना चाहती थी।

दक्षिण हरियाणा में औद्योगिक श्रमिक स्थानीय क्षेत्रों के साथ–साथ बाहर से भी आते हैं। पानीपत में, जो मुख्य रूप से अन्य राज्यों के श्रमिकों को रोजगार देने वाले पिटलूम और पावरलूम का एक बड़ा केंद्र था, औद्योगिक इकाइयों को संकट का सामना करना पड़ा है और औद्योगिक श्रमिकों की संख्या में वास्तव में कमी आई है। पहले की हुडडा सरकार में, पानीपत और गुड़गांव में मजदूरों के आंदोलनों का काफी बेरहमी से दमन किया गया था। श्रमिक नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जबकि श्रमिकों को अपने शोषण के खिलाफ विरोध करने और अपने कानूनी अधिकारों की मांग करने के लिए नौकरियों से बाहर निकाल दिया गया।

हरियाणा में चुनावी लड़ाई काफी तीखी थी और अंतर कम था। हालांकि आरएसएस–बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी की है, लेकिन वोट शेयर के मामले में दोनों मुख्य पार्टियों के बीच अंतर काफी कम है। आरएसएस–बीजेपी इसे एक बड़ी जीत के रूप में पेश कर रही है और अपने फासीवादी मार्च को गति देने के लिए, जो पिछले संसदीय चुनावों के बाद एक हद तक मद्धम हो चुका था, इसे प्रयोग में लाने की कोशिश कर रही है। आरएसएस–भाजपा इस परिणाम को अपनी जनविरोधी आर्थिक नीतियों के समर्थन और जन आंदोलनों पर फासीवादी दमन के समर्थन के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, यह चुनाव बीजेपी द्वारा जीतने की तुलना में कांग्रेस ने हारा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की कारगुजारी से एक दिलचस्प मोड़ यह आया कि यह वोट भाजपा के दस साल के कुशासन पर नहीं, बल्कि हुड्डा पर वोट बन गया।

मुख्य दावेदारों के बीच मामूली अंतर को देखते हुए, दोनों के बीच अंतर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के कारण सीटों के संदर्भ में बढ़ गया है। इसमें चुनावी प्रबंधन करने की पर्याप्त गुंजाइश थी जिसमें आरएसएस–भाजपा अन्य दलों से काफी आगे है। निर्दलियों को रणनीतिक तौर पर मैदान में उतारना और कांटे की टक्कर वाली सीटों पर जोड़–तोड़ करना जाहिर तौर पर उनका किला है। ईवीएम में हेरफेर एक बार फिर फोकस में आ गया है और चुनाव आयोग को सत्तारूढ़ आरएसएस–भाजपा की सेवा में काम करने के बजाय अन्य दलों द्वारा उठाए गए सभी संदेहों को दूर करना चाहिए। ईवीएम की कार्यप्रणाली के बारे में विशिष्ट शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिए और यदि चुनाव आयोग ऐसा करने में विफल रहता है, तो उच्च न्यायपालिका को इसमें कदम उठाना चाहिए।

इस चुनाव से यह स्पष्ट है कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होते हुए भी कांग्रेस को खासकर हिंदी पट्टी में भाजपा को हराना मुश्किल हो रहा है। इसका कारण यह है कि कांग्रेस अपना अभियान उन प्रमुख सामाजिक वर्गों के इर्द–गिर्द बनाती है, जिनका बहुमत आरएसएस–भाजपा के साथ है। हालांकि कांग्रेस नेता जाति जनगणना कराने जैसे सवाल उठाते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण में गंभीरता का अभाव है। पिछले चुनाव में भी आरएसएस–बीजेपी को बड़ा झटका वहीं लगा था जहां क्षेत्रीय पार्टियां आरएसएस–बीजेपी का मुकाबला कर रही थीं या विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रही थीं। ऐसा विशेषकर हिंदी भाषी प्रांतों में रहा।

चुनावी प्रतिस्पर्धा से परे, लेकिन उससे सामने आया सवाल, मेहनतकशों,– किसानों और मजदूरों की एकता बनाने का सवाल मुख्य चिंता का विषय है, खासकर प्रगतिशील और क्रांतिकारी ताकतों के लिए। अधिकांश किसानों (लगभग 87%) के पास छोटी जोत है और वे अपनी जमीन पर मेहनत करते हैं और यहां तक कि बाहर मजदूरी भी करते हैं। इनके और ग्रामीण श्रमिकों के भूमि माफिया सहित कॉरपोरेट कि विरुद्ध समान हित हैं। लेकिन शासक वर्ग की पार्टियाँ मेहनतकश जनता के इन वर्गों के बीच खाई बढ़ाती रहती हैं। हालाँकि, विदेशी और घरेलू कॉरपोरेट के इशारे पर किसानों और मजदूरों के खिलाफ बढ़ते हमले को देखते हुए इस एकता को बनाना और मजबूत करना बेहद जरूरी है। इस आक्रमण की जड़ साम्राज्यवादी व्यवस्था के गहराते संकट और इस स्थिति में अपने मुनाफों को अधिकतम करने के लिए कॉरपोरेट की तीव्र गति में निहित है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न देशों में फासीवादी ताकतों का विकास और मजबूती हुई है। उनका लाभ अधिकतम करने का अभियान मौजूदा लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ टकराव में आ रहा है, जिसे वे कम करना चाहते हैं। हमारे देश में फासीवादी ताकतें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अपने अभियान सहित विभिन्न माध्यमों से किसानों और मजदूरों के बीच एकता को रोकना चाहती हैं और इसके बल पर अपने फासीवादी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती हैं।

ये चुनाव एक बार फिर फासीवादी ताकतों के कदम को रोकने के लिए जन संघर्षों के महत्व को उजागर करते हैं। शासक वर्गों के फासीवादी मोड़ को चुनौती देने के लिए शोषितों और उत्पीड़ितों, मजदूरों और किसानों, युवाओं और महिलाओं और दलितों और आदिवासियों के संघर्षों को विकसित किया जाना चाहिए। साम्राज्यवाद के प्रभुत्व वाली वित्तीय पूंजी द्वारा भारतीय लोगों पर थोपी गई और बड़े पूंजीपति, बड़े जमींदार शासक वर्गों द्वारा लागू की गई नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ लोगों के संघर्ष को भारतीय मेहनतकश जनता के शोषण और उत्पीड़न के ढांचे को हिला देने के लिए विकसित किया जाना चाहिए। संघर्ष में लोगों की यह एकता फासीवाद के बढ़ते कदमों के खिलाफ वास्तविक सुरक्षा कवच होगी। मेहनतकश जनता के विभिन्न वर्गों के संघर्षों सहित जनसंघर्षों का निर्माण और विकास फासीवादी ताकतों के खिलाफ आंदोलन का मुख्य पहलू है।

(न्यू डेमोक्रेसी के अक्तूबर 2024 अंक में जम्मू–कश्मीर तथा हरियाणा के चुनाव परिणामों पर प्रकाशित टिप्पणी का हिन्दी अनुवाद)

पिलंजी (सरोजिनी नगर, नई दिल्ली) में निर्माण मजदूरों की सीवर में हुई मौत के लिए कम्पनी तथा सरकार जिम्मेदार : इफ्टू

अखबारों मे प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार नई दिल्ली में सरोजिनी गगर के पिलंजी में सीवर साफ करते समय 2 मजदूरों की मौत हो गई। इसकी जांच कराने इफ्टू की एक टीम सरोजनी नगर पिलंजी गाँव गई। वहां इलाके का मुआयना करने तथा मजदूरों बात करने पर पता चला कि यह एनबीसी (NBCC) की साईट है जो कि केन्द्र सरकार कम्पनी है। यह घटना वहां हुई जहां मजदूर रह रहे थे।

यह एक बहुत बड़ा प्लॉट है। वहां पर लगभग 1200 मजदूर रहते हैं। ये सभी टिन की शेड डाल कर रहते हैं। हर काम के अलग अलग ठेकेदार हैं। ज्यादातर काम अलग–अलग पेटी ठेकेदार कराते हैं। अलग अलग ठेकेदार के अलग अलग टिन शेड है हर शेड पर नम्बर डाला गया है। सभी शेड में आगे से नाली बह रही है जो बहुत ही गंदी है। सभी नाली का पानी एक सीवर में जा रहा था। वही सीवर जाम हो गया था। सीवर को साफ करने का कोई इंतजाम कम्पनी द्वारा नहीं किया गया। उसी सीवर के जाम को खोलने के लिए पहले एक मजदूर उतरा वो फंस गया तो फिर दूसरा मजदूर उतरा और फिर उसको बचाने के लिए एक तीसरा मजदूर गया उनको बचाने के लिए। पर वो सभी फंस गये और दो मजदूर की सीवर में मौजूद जहरीली गैस से मौत हो गई। मृतकों के नाम बबुद्र कुमार सिंह व राम आसरे है। तीसरा निर्माण मजदूर श्रीनाथ सोरेन है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

ये सभी मजदूर अलग अलग राज्यों से पेटी ठेकेदारों के जरिए से लाये गये हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से। इन मजदूरों के पास कोई भी कानूनी सुविधा तक नहीं है जैसे ESI, PF, न्यूनतम वेतन, नियत काम के घण्टे आदि तथा न ही कम्पनी या ठेकेदार का कोई आई कार्ड है। सभी मजदूरों से प्रतिदिन 12 घंटे काम कराया जाता है जिसमें महिला मजदूर भी शामिल है। इनको 12 घन्टे का प्रतिदिन 400 रूपये से लेकर 600 रुपये तक दिये जाते हैं। इन्हें बन्धुवा मजदूरों के तरह एक बाउण्ड्री में रखा गया है और इससे निकलने का सिर्फ एक गेट है।

यहाँ पता चलता है कि –

(1) मजदूर अमानवीय हालत में रहते हैं जहां गन्दगी का अम्बार लगा है। छोटी सी जगह बहुत से लोग रहने को मजबूर हैं। आलीशान बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी निर्माणकर्ताओं अर्थात मजदूरों को इंसानों के रहने के लायक न्यूनतम जरूरत वाली रिहाईश भी नहीं देती है। यह इल मजदूरों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण का स्पष्ट सबूत है।

(2) इन्हें कानूनी कोई सुविधा नहीं दी जाती है जिनका ऊपर उल्लेचा किया गया है। श्रम कानूनों का खुले आम उल्लंघन हो रहा है जबकि यह कंपनी केंद्र सरकार की है।

(3) दिल्ली में होने के बाद भी दिल्ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (DBOCWWB) में भी दन मजूदरों का पंजीकरण नहीं है।

(4) मजदूरों की सुरक्षा की कोई उपाय नहीं है न ही उनको सुरक्षा किट दिया जाता है जो हर निर्माण मजदूर को आवश्यक रुप से दिया जाना चाहिए।

अतः हम मांग करते हैं :

(क) मृत मजदूरों के परिवारों को कम्पनी तथा ठेकेदार के तरफ से 10–10 लाख रुपये दिये जायें और दिल्ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से 2–2 लाख रूपये दिये जायें।

(ख) मृतकों के परिवार में किसी आश्रित को नौकरी दी जाए।

(ग) घायल मजदूर को भी समुचित मुआवजा मिले।

(घ) सभी मजदूरों को ESI तथा PF की सुविधा दी जाये, व अन्य श्रम कानून लागू किये जाएं।

(ङ) सभी मजदूरों को सुरक्षा किट दिये जायें।

(च) सभी मजदूरों को रिहाईश के स्थान पर मूलभूत मानवीय जरूरतों के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाएं और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की हो।

(इफ्टू की दिल्ली कमेटी द्वारा 14 अक्टूबर, 2024 को जारी)

का. एस.एन. सिंह की 40वीं बरसी पर सासाराम (बिहार) में रैली एवं स्मृति सभा

मुशहरी सशस्त्र संघर्ष के राजनीतिक प्रणेता, सी0पी0आई0 (एम–एल) के प्रमुख संस्थापकों में से एक, पार्टी के भीतर वाम भटकाव के विरुद्ध जनदिशा के लिए संघर्ष के अगुआ और क्रांतिकारी जनदिशा के पथ प्रदर्शक एवं सी0पी0आई0 (एम–एल) के पूर्व महासचिव का. सत्यनारायण सिंह की 40वीं बरसी पर सासाराम (बिहार) में रैली एवं स्मृति सभा का आयोजन किया गया।

30 जनवरी 2023 को मुजफ्फरपुर (बिहार) में का. सत्यनारायण सिंह के 100वें जन्मदिन पर मुशहरी सशस्त्र किसान संघर्ष और उनकी कुल राजनीतिक भूमिका को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रेखांकित करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 23 अक्टूबर 2024 को उनकी 40वीं बरसी के मौके पर पुराने शाहाबाद जिला के सासाराम में रैली व स्मृति सभा आयोजित कर पार्टी ने अपनी कतारों को पार्टी इतिहास एवं क्रांतिकारी पार्टी निर्माण की जरूरत एवं देश में बढ़ते फासीवादी हमलों का मुकाबला करने के लिए का. एस.एन. सिंह की समझ एवं अपनाई गयी कार्य दिशा से परिचित कराने का प्रयास किया। का. सत्यनारायण सिंह का निधन 21 अक्टूबर 1984 को कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एकता प्रयास के दौरान विशाखापतनम (आन्ध्र प्रदेश) में हुआ था।

दिन के करीब 12 बजे शेरशाह पानी रौजा से एक जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से हाथों में झंडा–बैनर लिए हुए आए पुरुष–महिला मजदूर किसान शामिल थे। का0 सत्यनारायण सिंह अमर रहें; का0 सत्यनारायण सिंह हम तुम्हारी राह पर हैं; नक्सलवादी मुशहरी सशस्त्र किसान संघर्ष जिन्दाबाद; संशोधनवाद–नव संशोधनवाद मुर्दाबाद; फासीवादी हमलों को परास्त करो, आदि नारों से माहौल गूंज उठा। रैली सासाराम शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दिन के 1:30 बजे तकिया स्थित पटेल धर्मशाला के सभागार में पहुँचकर स्मृति सभा में तब्दील हो गई।

ससाराम : सभा से पहले जुलूस

का. एस. एन. सिंह की संकलित रचनाओं का विमाचन करते का. सुशांत झा

कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के जिला प्रवक्ता का. अयोध्या राम द्वारा का. सत्यनारायण सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं फूल चढ़ाने से हुई। सभा की अध्यक्षता पार्टी के राज्य प्रवक्ता डा. वी.के. पटोले ने की। का. पटोले ने का. एस.एन. सिंह के राजनीतिक जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों में लिखे गये आलेखों के संग्रह का विमोचन करने के लिए पार्टी के केन्द्रीय प्रवक्ता का. सुशान्त झा को आमंत्रित किया। इस मौके पर का. सत्यनारायण सिंह द्वारा लिखे गये आलेखों का उल्लेख करते हुए का. सुशान्त झा ने कहा कि देश की विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों, पार्टी के समक्ष उत्पन्न समस्याओं व अन्तर्विरोधों के बीच सत्यनारायण सिंह के द्वारा लिखे गये आलेखों का यह संग्रह हमारी पार्टी कतारों व समग्र क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन के लिए दिशा सूचक व मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। का. सुशान्त झा ने का0 सत्यनारायण सिंह द्वारा अपने राजनीतिक जीवन में लिए गये महत्वपूर्ण फैसलों और घटनाओं का भी उल्लेख किया। खासकर पार्टी के भीतर वाम भटकाव के विरुद्ध जनदिशा की स्थापना के लिए उनके द्वारा किये गये संघर्षों पर विशेष चर्चा की।

इस मौके पर स्मृति सभा को सम्बोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के प्रान्तीय अध्यक्ष का0 रामवृक्ष राम ने मुशहरी सशस्त्र किसान संघर्ष की यादों को साझा करते हुए कहा कि मुशहरी सशस्त्र किसान संघर्ष के नेताओं में शहीद का. राजकिशोर सिंह एवं का. उमाधर सिंह आदि थे किन्तु उसके राजनीतिक प्रणेता का. सत्यनारायण सिंह थे। स्मृति सभा में इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स के प्रान्तीय महासचिव का. लालू राम ने कहा कि मैं अपनी किशोरावस्था में का. सत्यनारायण सिंह से मिला था, जब 1982 में नोखा थाना ग्राम कुझी के भूमिहीनों और पुलिस के बीच एक निर्दोष व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर टकराव हुआ था। पुलिस को वहां से भागना पड़ा था। इस घटना के बाद पुलिस ने भारी संख्या में जाकर दर्जनों लोगों के विरुद्ध झूठे मुकदमें किये और जेल में बंद कर दिया। उस समय का. सत्यनारायण सिंह सासाराम मंडल कारागार में बंद सभी लड़ाकू भूमिहीनों से मिलने के लिए आए और उनका साहस बढ़ाया। इसके अलावा का0 एस.एन. सिंह तत्कालीन बिहार जिसमें झारखंड भी शामिल था के अग्रणी मजदूर नेताओं में थे।

स्मृति सभा में शामिल होने के लिए अभिनन्दन करते हुए अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव का0 आशीष मित्तल ने कहा कि का0 सत्यनारायण सिंह ने अपना सारा जीवन शोषितों–पीड़ितों के मुक्ति आन्दोलन को समर्पित कर दिया था। उन्हें क्रांतिकारी जनदिशा के पथ प्रदर्शक के साथ देश में लागू इमरजेन्सी के दौरान इंदिरा तानाशाही के खिलाफ तमाम लोकतांत्रिक एवं जनवादी शक्तियों के एकजुट विरोध के लिए भी याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज देश में आरएसएस–बीजेपी के नेतृत्वाधीन मोदी सरकार के फासीवादी हमलों को देश की धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक ताकतें झेल रही हैं। अल्पसंख्यकों को खासकर निशाना बनाया जा रहा है। देश में अंधराष्ट्रवाद की हवा बहाकर आम जनता को आपस में लड़ाने के बीच देशी व विदेशी कारपोरेटों को लूट की खुली छूट दी गई है। फासीवादी हमलों के ख्लिाफ जनवादी, लोकतांत्रिक एवं क्रांतिकारी ताकतों को उन्होंने एकजुट होने का आह्वान किया।

सभा के आखिरी में सभाध्यक्ष का. वी. के. पटोले ने कहा कि का. सत्यनारायण सिंह के राजनीतिक जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। वे एक बेहतरीन वक्ता के साथ–साथ जबरदस्त पहलकदमी वाले इंसान थे। वे जिस बात को सही समझते थे, मजबूती से कदम बढ़ाते थे और जब वे अपनी भूल को महसूस कर लेते थे तब वे उसे बेहिचक स्वीकार करते हुए सुधारते भी थे। उनके राजनीतिक जीवन में दो बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने एहसास होते ही अपनी गलती को सुधारा। 1980 में शासक वर्गों के साथ संयुक्त मोर्चे के प्रश्न पर करीब दो सालों बाद ही हुई भूल का एहसास होने के बाद उन्होंने खुद को जिम्मेदार माना और उसे सुधारने की दिशा में आगे बढ़ गये। उसके पूर्व वाम भटकाव के विरुद्ध उनकी आत्मालोचना रिपोर्ट भी इस बात का सबूत है कि अपनी गलतियों के लिए आत्मआलोचना से सत्यनारायण सिंह को कोई परहेज नहीं था।

डा. पटोले ने कहा कि मात्र 61 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया जबकि पार्टी और देश को अभी उनकी और जरूरत थी। हम जहां आज रोहतास जिला के सासाराम में उनकी स्मृति सभा कर हैं, यह जिला पुराने शाहाबाद जिला का ही हिस्सा है जहां का. सत्यनारायण सिंह ने अपने शुरु के जीवन में आन्दोलन किये थे। सभाध्यक्ष ने जवजनवादी क्रांति को पूरा करने और फासीवादी हमलों को परास्त करने के आह्वान के साथ मंच से सभा समापन की घोषणा की।

महिला न्याय के लिए अभया मंच का गठन

पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों के संयुक्त मंच ने नागरिक समाज के लगभग 80 जन संगठनों के साथ मिलकर ललित कला अकादमी कोलकाता के सभागार में 'अभया मंच' की स्थापना की। 28 अक्टूबर 2024 को गठित इस मंच के संयोजक मनीषा अदक, डॉक्टर पुण्यव्रत गुण और तमोनाश चौधरी को चुना गया। इस गठन के बाद से पश्चिम बंगाल के कई और मंच और जन संगठन भी इसमें शामिल हो गए हैं।

अभया मंच का उद्देश्य :

– अभया के लिए उचित और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना।

– समाज के सभी क्षेत्रों में समग्र अपराधीकरण को खत्म करने और अभया जैसे मामलों को रोकने के लिए भ्रष्टाचार और प्रशासन द्वारा पोषित व समर्थित खतरों की सोच और संस्कृति के खिलाफ आंदोलन तैयार करना।

– महिलाओं और हाशिए पर पड़े लिंगों पर हमलों के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होना।

कार्यक्रम :

कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की योजना पहले ही बनाई जा चुकी है, जिसमें जयनगर (दक्षिण बंगाल) से जयगांव (उत्तर बंगाल) तक एक जत्था लॉन्ग मार्च आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम का विस्तृत विवरण जल्द ही घोषित किया जाएगा। इससे पूर्व 26 अक्टूबर को फोरम ने पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट द्वारा सीबीआई के सीजीओ कंपलेक्स तक आयोजित रैली में भाग लिया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने मशालों के साथ मार्च किया और नारे लगाए – 'हमें न्याय के लिए कब तक इंतजार करना होगा, सीबीआई आपको जवाब देना होगा।' 9 नवंबर को एक सामूहिक बैठक का भी आयोजन किया गया है, जिसमें नागरिक संगठन के लोग प्रशासन और हत्यारों के खिलाफ आरोप पत्र पेश करेंगे।

(यहां पश्चिम बंगाल में अभया मंच के गठन के बारे में प्राप्त एक रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है।)

पत्रिका के नियमित प्रकाशन के लिए सभी पाठकों से अनुरोध

- *पत्रिका के लिए लेख व रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें।*
- *पत्रिका के बारे में अपने सुझाव भेजें।*
- *कृपया पत्रिका की प्रतियों की राशि समय पर पहुंचाएं।*
- *लेख, रिपोर्ट, सुझाव तथा राशि पत्रिका के पते पर भेजें।*

पंजाब: धीमी खरीद और अनाज के उठान में सुस्ती से किसान परेशान

पंजाब सरकार के 1 अक्टूबर से खरीद जारी होने के दावे के बावजूद खरीफ फसल का उठान नहीं हो रहा था। बाजारों में अनाज के बड़े–बड़े ढेर लगे हुए थे। ऐसी स्थिति ने एसकेएम को पंजाब सरकार से उलझने पर मजबूर कर दिया।

एसकेएम ने इस स्थिति से निपटने की कोशिश की और 7 अक्टूबर को ही पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलने का फैसला किया था।

7 अक्टूबर को एसकेएम के दो प्रतिनिधि मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और उनसे मिलने की मांग की। लेकिन पुलिस अधिकारी टाल–मटोल करने लगे। एसकेएम ने उनके घर के सामने धरने पर बैठने की धमकी दी। तब सीएम को मुलाकात के लिए राजी होना पड़ा, लेकिन मुलाकात का स्थान पंजाब भवन तय किया गया। कृषि मंत्री, अधिकारियों के साथ पंजाब भवन आये और धान की फसल की खरीद कुशलतापूर्वक करने का वायदा किया। लेकिन एसकेएम ने सीएम द्वारा एसकेएम से मिलने की प्रतिबद्धता के उल्लंघन पर अपना विरोध दर्ज कराया और खरीद शुरू होने तक पंजाब भवन में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अंततः राज्य भर की कई अनाज मंडियों में खरीद शुरू हो गई और इसलिए एसकेएम ने उसी देर शाम से विरोध वापस ले लिया।

13 अक्टूबर को 'चक्का जाम'

खरीद शुरू हुई लेकिन अटक गई। दो दिनों के बाद, एसकेएम, कमीशन एजेंटों और राइस मिलर्स ने 13 अक्टूबर को 3 घंटे का रोड ब्लॉक करने का फैसला किया। पंजाब के 22 जिलों में 125 स्थानों पर चक्का जाम किया गया। कीर्ति किसान यूनियन ने 16 जिलों में भाग लिया।

18 अक्टूबर को सीएम आवास के सामने धरना

सड़क जाम की घोषणा के बाद पंजाब के मुख्य सचिव ने एसकेएम को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। 11 अक्टूबर की बैठक में एसकेएम ने 14 प्रस्ताव रखे। मुख्य सचिव ने प्रस्तावों पर विचार के लिए अगली बैठक 14 अक्टूबर तय की, लेकिन राइस मिलर्स और कमीशन एजेंट अपने अवसरवादी चरित्र के कारण केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करने चले गए, पर उन्हें खोखले वायदों के अलावा कुछ नहीं मिला। वे किसान नेताओं को विश्वास में लिए बिना उस बैठक में शामिल हुए।

एसकेएम ने उनके दृष्टिकोण की आलोचना की, लेकिन मुद्दे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने सीएम आवास के सामने एक संयुक्त विरोध प्रदर्शन की घोषणा की।

8 अक्टूबर को चंडीगढ़ जा रहे किसान नेतृत्व को पुलिस ने तरह–तरह से परेशान किया। पुलिस ने चंडीगढ़ के सभी प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी। इसके बावजूद करीब 350 प्रदर्शनकारी तय बिंदु तक पहुंचने में कामयाब रहे। कमीशन एजेंटों की उपस्थिति नगण्य थी। राइस मिलर्स इस कार्यक्रम से पूरी तरह चूक गए। मजदूर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, हालांकि उनकी उपस्थिति कम थी।

जब प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास की ओर मार्च किया तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और 19 अक्टूबर को सीएम से मिलने का पत्र सौंपा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने वहीं धरना शुरू कर दिया और घोषणा की कि जब तक सीएम खुद उनसे नहीं मिलेंगे तब तक कोई अगला फैसला नहीं लिया जाएगा।

प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की कि जिन किसानों को रास्ते में हिरासत में लिया गया है, उन्हें विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। दूसरी ओर, हिरासत में लिए गए किसानों ने विभिन्न तरीकों से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिये और इसके परिणामस्वरूप सरकार को सभी हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा करना पड़ा तथा उन्हें विरोध में शामिल होने की अनुमति दी गई। 18 अक्टूबर की रात किसान भवन में बिताई गयी, यहीं पर लंगर की व्यवस्था भी की गई।

19 अक्टूबर को सीएम, वित्त एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री और खरीद से जुड़े अधिकारियों ने पंजाब भवन में एसकेएम के साथ बैठक की। सीएम ने माना कि खरीद में कमियां हैं और उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि दो दिन के अंदर खरीद शुरू हो जाएगी। नियमों में छूट मिलने के बावजूद धान के लिए जगह नहीं देने वाले राइस मिलर्स पर गाज गिरेगी।

सीएम द्वारा इस प्रकार आश्वासन दिए

(शेष पृष्ठ 8 पर)

18 अक्तूबर 2024 : चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री निवास के समक्ष किसानों के धरने का एक दृश्य

इफ्टू : अभया को न्याय के लिए संघर्ष के साथ एकजुटता का वक्तव्य

इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (इफ्टू) की राष्ट्रीय कमिटी ने 19 और 20 अक्टूबर 2024 को मंचिर्याल (तेलंगाना) में अपनी बैठक में, 22 अक्टूबर 2024 को पेनडाउन संघर्ष के लिए WBJDF (पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फेडरेशन) के आह्वान के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल कोलकाता की एक महिला डॉक्टर के साथ 'कार्यस्थल पर यौन हिंसा और हत्या' के संदर्भ में उनकी ज्वलंत मांगों को पश्चिम बंगाल सरकार तुरंत हल करे इसके लिए WBJDF ने यह आह्वान किया है। उस डॉक्टर (वे उसे अभया कहते हैं) के लिए न्याय के लिए और पश्चिम बंगाल के सरकारी स्वास्थ्य ढांचे में भ्रष्टाचार के उस गठजोड़ जिसके कारण यह घटना हुई की समाप्ति करने के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं।

अभया के बलात्कार और हत्या की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद से दो महीने से अधिक समय बीत चुका है। सीबीआई अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे सौंपते हुए जोरदार तरीके से कह रही है कि जांच सौंपे जाने से कुछ दिन पहले घटनास्थल पर मौजूद सबूत नष्ट कर दिए गए थे। जूनियर डॉक्टरों ने सीबीआई को अपने पास मौजूद सभी सबूत सौंप दिए हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह साबित हो चुका है कि घटना के कुछ दिन बाद आरजी कर अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग पर हमला करने वाले गुंडों को पुलिस ने नहीं रोका और उनका मकसद केवल सबूत नष्ट करना और घटना से जुड़ी जानकारी रखने वालों को आतंकित करना ही हो सकता था। इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सब एक 'सिविक वालंटियर' को बचाने के लिए नहीं किया गया हो सकता था। फिर भी जांच को लंबा खींचा जा रहा है।

'न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है'। IFTU की राष्ट्रीय कमिटी 'सर्वोच्च न्यायालय से मांग करती है कि वह इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा तत्काल, समयबद्ध तरीके से पूरी किया जाना सुनिश्चित करे ताकि बलात्कार/सामूहिक बलात्कार और हत्या तथा इस मामले को दबाने अथवा इसकी साजिश में शामिल लोगों की पहचान की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए।' हम निष्पक्ष, वैज्ञानिक, त्वरित जांच और निश्चित सजा की मांग करते हैं।

कामकाजी महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा सभी कामकाजी तबकों के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है, जिसमें डॉक्टर, अस्पताल कर्मचारी, फैक्ट्री कर्मचारी, निर्माण श्रमिक, सफाई कर्मचारी, पीएसयू, सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले ठेका और आकस्मिक कर्मचारी, बीड़ी श्रमिक, स्कूल शिक्षक, सिने कलाकार या अन्य क्षेत्र शामिल हैं– यह सूची लंबी है। यह विशेष रूप से सच है अगर कामकाजी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खड़ी होने की हिम्मत करती हैं।

IFTU की राष्ट्रीय कमिटी अपनी सभी इकाइयों से WBJDF के अभया को तत्काल न्याय दिलाने की मांग के लिए संघर्ष का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम लेने का आह्वान करती है। हम सभी महिला श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा की भी मांग करते हैं।

(इफ्टू की राष्ट्रीय कमिटी की अध्यक्ष अपर्णा तथा महासचिव टी. श्रीनिवास द्वारा 20 अक्टूबर 2024 को जारी)

इफ्टू की राष्ट्रीय कमिटी के आवाहन पर देश भर में विरोध प्रदर्शन किये गये। इनमें से कुछ के फोटो हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं।

30.10.24: गौतमी एग्रो इंडस्ट्रीज ऐलुरु ग्रामीण में महिला मजदूरों का प्रदर्शन

30 अक्तूबर 2024: इफ्टू राष्ट्रीय कमेटी के आवाहन पर विशाखापत्तनम में इफ्टू तथा पी.ओ.डब्ल्यू. द्वारा संयुक्त धरना। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते इफ्टू के आंध्र प्रदेश उपाध्यक्ष का. एम. वैंकटेश्वरालु

कालाहस्ती (चित्तूर) में आंगनवाड़ी महिलाओं द्वारा प्रदर्शन

रिसड़ा (प. बंगाल) में मजदूरों द्वारा विरोध प्रदर्शन

अभया को न्याय- सुप्रीम कोर्ट सीबीआई द्वारा समयबद्ध तरीके से जांच पूरी किया जाना सुनिश्चित करो। देरी से न्याय का मतलब है न्याय से इन्कार ! सीबीआई-अभया मामले में बलात्कार और हत्या की साजिश या अपराध को छिपाने या अपराध करने के सभी दोषियों का खुलासा करे। दोषियों को सजा दें!

ज्पारत में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों में 27 प्रतिशत सजा दर! आश्चर्यजनक और भयानक? लेकिन देखिए कि 9 अगस्त को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की 31 वर्षीय डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की जांच कैसे की जा रही है। यह पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट द्वारा अभया जैसा कि उन्होंने उसका नाम रखा है, को न्याय दिलाने के लिए ढाई महीने लंबे संघर्ष के बावजूद है। उनका संघर्ष जारी है। पश्चिम बंगाल में लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा हो रहा है। इसी तरह सभी सरकारें, केंद्र और राज्य, इसी तरह अदालतें, व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के दोषियों की रक्षा करती हैं।

पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि अभया को इस तरह से दंडित किया गया क्योंकि उसने भ्रष्टचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। माता–पिता ने कहा कि पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन पर दबाव डाला और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया। उसके सहयोगियों को न्यायिक जांच के लिए लड़ना पड़ा। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में नष्ट किए गए अपराध स्थल के बारे में बात की है जबकि मामला कोलकाता पुलिस के पास था। 14 अगस्त को एक विशाल भीड़ ने इमरजेंसी बिल्डिंग पर हमला किया जिसमें हत्या हुई थी और इसके कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया – पश्चिम बंगाल पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और पुलिस आयुक्त ने पुलिस के इस काम का बचाव किया। प्रिंसिपल और पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी को अपराध स्थल के पास के कमरे का 'पुनर्निर्माण' करने के लिए हस्ताक्षरित आदेश दिए। कमरे को तोड़ दिया गया था, हालाँकि पुलिस अपराध स्थल की प्रभारी थी! प्रिंसिपल को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें देश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज में उसी पद पर स्थानांतरित कर दिया! राज्य सरकार और उसकी पुलिस ने इस तरह से काम किया।

हाई कोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया। यह दो महीने से अधिक समय पहले की बात है। इतना संवेदनशील मामला, लेकिन सीबीआई जांच में देरी हो रही है! यह सुप्रीम कोर्ट में बड़े–बड़े दावे करती है और जजों को सीलबंद लिफाफे सौंपती है, लेकिन जांच पूरी नहीं करती। इसने सबूत नष्ट करने के लिए प्रिंसिपल और स्थानीय थाने के एसएचओ को गिरफ्तार किया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को नहीं, जिन्होंने उसी शाम हत्या स्थल के 'पुनर्निर्माण' के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। पुलिस आयुक्त की भूमिका स्थापित है, लेकिन सीबीआई निष्क्रिय है। इस तरह के उच्च स्तरीय कवर अप निश्चित रूप से एक 'नागरिक स्वयंसेवक' की रक्षा के लिए नहीं हो सकता, जिसे पश्चिम बंगाल पुलिस और सीबीआई दोनों ने अब तक अपराध का कथित 'एकमात्र' दोषी माना है।

'न्याय में देरी न्याय से इनकार'

यह बात सभी जानते हैं कि मोदी सरकार और ममता सरकार के बीच हर मुद्दे पर तीखी बहस होती है। फिर भी इस मुद्दे पर जो पूरे देश को आंदोलित कर रहा है, केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई जांच पूरी करने में असमर्थ है! यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महिला पहलवानों के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और शक्तिशाली लोगों द्वारा यौन हिंसा के मामलों की लंबी सूची पर मोदी सरकार का रिकॉर्ड है, चाहे वह उन्नाव हो, हाथरस हो, कठुआ हो आदि। कोई भी सरकार शक्तिशाली लोगों द्वारा यौन हिंसा के मामलों में लोगों के संघर्ष के बिना न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकती। यह केवल हमारा व्यापक संघर्ष ही है जो न्याय सुनिश्चित करा सकता है। WBJDF और उस राज्य के लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। आइए हम महिलाओं के बीच ऊर्जावान अभियान चलाएं। आइए हम समाज के सभी लोकतांत्रिक वर्गों को संगठित करें।

'हम देश भर की महिलाओं से 4 नवंबर 2024 को जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान करते हैं। 5 नवंबर आर जी कर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की संभावित तारीख है।' आइए हम सभी महिला संगठनों, ट्रेड यूनियनों, लोकतांत्रिक संगठनों को विरोध में आगे आने के लिए संगठित करें।

'आइए हम सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट से आह्वान करें–'

'सीबीआई को तत्काल, समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करने का निर्देश दें।'

''अभया के बलात्कार और हत्या के सभी दोषियों, मामले को छिपाने के दोषियों और बलात्कार और हत्या की साजिश और/या मामले को छिपाने की साजिश के सभी दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।'

'अभया को न्याय मिले!''

अखिल भारतीय समन्वय

प्रोग्रेसिव अङ्गर्गेनाइजेशन आफ वूमेन (POW) आंध्र प्रदेश

प्रोग्रेसिव अङ्गर्गेनाइजेशन आफ वूमेन (POW) तेलंगाना

स्त्री जागृति मंच (IJM) पंजाब

प्रगतिशील महिला संगठन (PMS) दिल्ली

जी.एन. साईबाबा को श्रद्धांजलि

सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी कामरेड जी.एन. साईबाबा के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त करती है। कामरेड जीएन साईबाबा ने 12 अक्टूबर की शाम निम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। जीएन साईबाबा दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज में अंग्रेजी के सहायक प्रोफेसर थे। वह देश में न्याय पूर्ण और समतावादी समाज के लिए अथक संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे। एक मामले में लंबे समय तक जेल में रहने जिसमें बाद में उन्हें रिहा किया गया, के कारण उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। एक सामान्य सर्जरी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसका प्रमुख कारण लंबे समय तक जेल में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण उनके शरीर को हुई क्षति थी। 90 प्रतिशत विकलांग होने के बावजूद उनकी अपील लंबे समय तक लंबित रही और उन्हें जमानत नहीं दी गई।

उनकी मृत्यु एक तरह से राज्य द्वारा की गई हत्या है। उन्होंने एक सच्चे योद्धा की भावना से इन सभी कठिनाइयों को सहन किया। उनकी लड़ाकू भावना ने एकांत कारावास में रखे जाने और आवश्यक चीजों से भी वंचित किए जाने सहित अनगिनत कष्टों को उन्होंने सहन किया। कई बीमारियों के अलावा वह अपने कारावास की अवधि के दौरान कोविड़ से भी पीड़ित रहे। उनकी मृत्यु ने एक बार फिर भारतीय राज्य का अमानवीय चेहरा दिखाया है। इससे पहले 84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी जो इसी तरह यूएपीए के तहत जेल में बंद थे, उनके जीवन के लिए आवश्यक प्रावधानों और सुविधाओं की सुनवाई तक अदालत में नहीं हो सकी थी।

'जमानत नियम है और जेल अपवाद' के बड़े–बड़े दावों के बावजूद भारतीय न्यायपालिका यूएपीए के मामलों में जमानत देने में हिचकती रही है। उच्च न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता पर राज्य की कथित सुरक्षा को प्राथमिकता देती रही है। कुछ लोग मुकदमों की प्रतीक्षा में जेलों में मर गए और कई अभी भी इस काले कानून के तहत जेलों में बंद पड़े हैं। का. साईबाबा की मृत्यु एक बार फिर यूएपीए को निरस्त करने की लड़ाई को तेज करने के महत्व को उजागर करती है, जिसे कानून की किताब में नहीं होना चाहिए।

उनके निधन से दबे कुचले लोगों ने एक सच्चा दोस्त और एक योद्धा खो दिया है और क्रांतिकारी आंदोलन को इससे बड़ी क्षति हुई है। सीपीआई (एम–एल) न्यू डेमोक्रेसी जीएन साईबाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। उनका काम अमर रहेगा। शासकों ने उन्हें शारीरिक रूप से भले ही समाप्त कर दिया हो, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए वे जिए और मरे, वह आगे बढ़ता रहेगा और बड़ी संख्या में लड़ाकों को आकर्षित करेगा हालांकि क्रांतिकारी परिवर्तन हमेशा की तरह उच्च कीमत वसूलेगा।

(सीपीआई (एमएल)-न्यू डेमोक्रेसी द्वारा 12 अक्टूबर 2024 को जारी)

पंजाबः धीमी खरीद और अनाज के उठान में सुस्ती से किसान परेशान

(पृष्ठ 7 का शेष)

जाने के बाद, एसकेएम ने विरोध प्रदर्शन को चार दिनों के लिए स्थगित कर दिया और घोषणा की कि अगली कार्रवाई की घोषणा 24 अक्टूबर को की जाएगी।

25 अक्टूबर को फिर 'चक्का जाम'

धीमी खरीद और फसल उठाने में कोई प्रगति नहीं होने के कारण, एसकेएम ने 25 अक्टूबर को फिर से चक्का जाम की घोषणा की। उस दिन राज्य भर में 150 स्थानों पर कॉल अमल होती देखी गई। इस विरोध ने सरकार को एक ही दिन में 2.5 लाख मीट्रिक टन की खरीद करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद खरीद शुरू हो गयी है।

29 अक्टूबर को डीसी कार्यालयों का घेराव

एसकेएम ने राज्य भर में डीसी कार्यालयों का भी घेराव किया। कई जगहों पर किसानों को एमएसपी से नीचे धान बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसानों को कथित तौर पर 70 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की कटौती करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कई बाजारों में, जहां खरीद सुस्त है किसानों को अभी भी स्थानीय विरोध प्रदर्शनों में संगठित किया जा रहा है। केंद्र और पंजाब सरकार के दावे कि समय पर एक–एक दाना खरीदने की योजना है, विफल हो गई है। मोदी सरकार की ऐतिहासिक हार, जब उसे तीन कॉरपोरेट समर्थक कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था, के कारण वह पंजाब और हरियाणा के किसानों को परेशान कर रही है।

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar

Monthly

Balmukand Khand,
Girinagar,
New Delhi-110019

Hindi Organ of CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87

Book Post

To

_____

_____

_____

_____

_____

_____

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-110019 से मुद्रित तथा प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार